



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-01042020-218982
CG-MH-E-01042020-218982

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2020/चैत्र 11, 1942

No. 142]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2020/CHAITRA 11, 1942

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

(मानव संसाधन विभाग)

(प्रधान कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 27 मार्च, 2020

एफ. सं. सीओ:ईआरडी:1071:2020 (ई).—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5), की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित, धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श और केन्द्र सरकार की पिछली मंजूरी के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :-

- (1) इन विनियमों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2020 कहा जा सकता है।
(2) इन विनियमों में अन्यथा वर्णित प्रावधानों को छोड़कर इन्हें 1 नवंबर, 2012 के दिन से प्रभावी, समझा जाएगा।
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 (इसके बाद जिन्हें उक्त विनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के विनियम 3 में, — खंड (एफ) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

‘(एफ) “परिवार” का अर्थ है अधिकारी का पति या पत्नी, पूरी तरह से निर्भर अविवाहित बच्चे (सौतेले बच्चे और कानूनी तौर पर अपनाये गये बच्चों सहित), चालीस प्रतिशत या अधिक निःशक्तता के साथ शारीरिक रूप से विकलांग भाई या बहन, विधवा पुत्रियाँ तथा आश्रित तलाकशुदा या अलग हो गयी बेटी, बहनें जिसमें अविवाहित या विधवा या परित्यक्त या पति से अलग हो गयी या विधवा बहनें शामिल हैं तथा अधिकारी पर पूर्णतः आश्रित माता-पिता तथा किसी महिला अधिकारी के मामले में उसके नैसर्गिक माता-पिता या सास-ससुर, परंतु दोनों नहीं, शामिल हो सकते हैं।

स्पष्टीकरण— “पूर्णतः आश्रित” से आशय परिवार के उस सदस्य से है जिसकी आय रु. 10,000/- प्रति माह से अधिक नहीं है तथा यदि पूर्णतः आश्रित परिवार में माता-पिता हैं तो यदि माता-पिता में से एकया माता-पिता दोनों की कुल आय रु. 10,000 प्रति माह से अधिक हो, तो माता-पिता दोनों को पूरी तरह से अधिकारी पर निर्भर नहीं माना जाएगा।

3. उक्त विनियमों के विनियम 4 में, उप-विनियम (6) हेतु निम्नलिखित विनियम सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

"(6) 1 नवंबर, 2012 से, प्रत्येक ग्रेड के सापेक्ष निर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होगा:

(ए) उच्च कार्यपालक ग्रेड

वेतनमान VII = रु. 76520 – 2120/4 – 85000

वेतनमान VI = रु. 68680 – 1960/4 – 76520

(बी) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड

वेतनमान V = रु. 59170 – 1650/2 – 62470 – 1800/2 – 66070

वेतनमान IV = रु. 50030 – 1460/4 – 55870 – 1650/2 – 59170

(सी) मध्यम प्रबंधन ग्रेड

वेतनमान III = रु. 42020 – 1310/5 – 48570 – 1460/2 – 51490

वेतनमान II = रु. 31705 – 1145/1 – 32850 – 1310/10 – 45950

(डी) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड

वेतनमान I = रु. 23700 – 980/7 – 30560 – 1145/2 – 32850 – 1310/7 – 42020

स्पष्टीकरण:- प्रत्येक अधिकारी जो 31 अक्टूबर, 2012 को लागू वेतनमानों से विनियमित होता है, 1 नवंबर, 2012 के इस उप-विनियम में निर्धारित वेतनमान में स्तर से स्तर के आधार पर फिट किया जाएगा, अर्थात् तत्संबंधित स्तरों पर पहले चरण से संबंधित चरणों पर और वेतन वृद्धि सामान्य रूप से आबिकी तारीख, अन्यथा निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर, पर आएगी.

- (7) उप-विनियम (1), (2), (3), (4), (5) और (6) में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए सर्वदा इन सभी ग्रेड में अधिकारियों का सेवारत होना आवश्यक है.

- (8) 01 नवंबर, 2012 से प्रभावी, अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ते का भुगतान किया जाएगा:

वेतनमान I-III = मूल वेतन का 7.75% और उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान IV-V = मूल वेतन का 10% और उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VI-VII = मूल वेतन का 11% और उस पर लागू महंगाई भत्ता

- (9) 31 मार्च 2020 को और उसके बाद से उच्च कार्यपालक ग्रेड में मुख्य महाप्रबंधक पद का वेतनमान व विशेष भत्ता निम्नानुसार होगा:

(ए) उच्च कार्यपालक ग्रेड

वेतनमान VIII = रु. 1,03,000 – 2,700/3 – 1,11,100 – 2,800/1 – 1,13,900

(बी) विशेष भत्ता

वेतनमान VIII = मूल वेतन का 11% और उस पर लागू महंगाई भत्ता

बशर्ते कि इस उप-विनियम में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए सर्वदा इन सभी ग्रेड में अधिकारियों का सेवारत होना आवश्यक है.

नोट: उपरोक्त उप-विनियम (8) व (9) में वर्णित विशेष भत्ते और उस पर लागू महंगाई भत्ता को सेवा निवर्तन लाभों यथा न्यू पेंशन स्कीम सहित पेंशन, भविष्य निधि व ग्रेजुटी के लिए संगणित नहीं किया जाएगा".

4. उक्त विनियमों के विनियम 5 में,-

(i) उप विनियम (1), हेतु निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) विनियम 4 के उप-विनियम (6) के प्रावधानों के अधीन, पर और 1 नवंबर, 2012 को एवं से वेतनवृद्धियां निम्नलिखित के अधीन दी जाएंगी, अर्थात् :-

(ए) विनियम 4 के उप-विनियम (6) में निर्धारित वेतनमानों में निर्दिष्ट संबंधित वेतनवृद्धियां, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन वार्षिक आधार पर प्रोद्भूत होंगी और जिस माह में देय है, उस माह के पहले दिन प्रदान की जाएगी;

(बी) वेतनमान I एवं वेतनमान II के अधिकारी, वेतनमान में अधिकतम उच्चतर वेतनमान प्राप्त करने के 1 वर्ष बाद उन्हें नीचे (सी) में निर्दिष्ट अनुसार अगले उच्चतम वेतनमान में गतिरोध वेतनवृद्धि सहित वेतनवृद्धि प्रदत्त की जाएगी. बशर्ते कि वे भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार दक्षतारोध को पार करने के अध्ययीन हैं;

(सी) उपर्युक्त (बी) में संदर्भित कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी के वेतनमान I के अधिकारी जो अधिकतम उच्चतर वेतनमान प्राप्त कर मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II में पहुंच गए हैं वह सेवा के प्रत्येक 3 वर्ष पूर्ण होने पर 4 गतिरोध वेतन वृद्धि के पात्र होंगे, जिनमें प्रथम दो रु. 1310/- प्रत्येक एवं अगली दो रु. 1460/- प्रत्येक के होंगी;

(डी) उपर्युक्त (बी) में संदर्भित मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II के वे अधिकारी जो अधिकतम उच्चतम वेतनमान प्राप्त कर मध्यम प्रबंधन वेतनमान श्रेणी III पहुँच गए हैं, सेवा के प्रत्येक 3 वर्ष पूर्ण होने पर रु. 1460/- प्रत्येक की 3 गतिरोध वेतन वृद्धि और रु. 1460/- की चौथी गतिरोध वेतन वृद्धि की पात्रता तीसरी गतिरोध वेतन वृद्धि प्राप्त करने के दो वर्ष के बाद होगी।

बशर्ते कि ऐसे अधिकारी जो तीसरी गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के बाद दो वर्ष या अधिक पूर्ण कर चुके हैं, उनको चौथी गतिरोध वेतन वृद्धि 01 मई, 2015 से प्राप्त होगी;

(ई) अधिष्ठायी मध्यम प्रबंधन श्रेणी III के अधिकारी (जो मध्यम प्रबंधन ग्रेड III में नियुक्त हुए हों या पदोन्नत हुए हों) सेवा के प्रत्येक 3 वर्ष पूर्ण होने पर रु. 1460/- प्रत्येक के 3 गतिरोध वेतन वृद्धि के पात्र होंगे और ऐसे अधिकारी जो तीसरी गतिरोध वेतन वृद्धि प्राप्त करने के बाद 01 मई, 2015 को दो या अधिक वर्ष पूर्ण कर चुके हैं वे रु. 1460/- की चौथी गतिरोध वेतन वृद्धि प्राप्त के पात्र होंगे, तथा रु. 1460/- की पाँचवी गतिरोध वेतन वृद्धि चौथी गतिरोध वेतन वृद्धि प्राप्त करने के दो वर्ष के बाद पात्र होंगे बशर्ते कि वे अधिकारी जिन्होंने चौथी गतिरोध वेतन वृद्धि प्राप्ति के बाद दो वर्ष पूर्ण कर लिए हैं उन्हें पाँचवी गतिरोध वेतन वृद्धि 01 मई, 2015 के प्रभाव से प्रदान की जाएगी।

(एफ) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV के अधिकारी, वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के बाद 01 मई, 2015 से तीन वर्षों की सेवा पूर्ण करने पर रु. 1650 की एक गतिरोध वेतन वृद्धि के पात्र होंगे;

बशर्ते कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने प्रस्तावित पदोन्नति को अस्वीकार किया हो उन्हें यह गतिरोध वेतन वृद्धि प्रदान नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण – इस उप-विनियम के तहत अगले उच्चतर वेतनमान में इस तरह की वेतनवृद्धि पदोन्नति नहीं होगी और अधिकारियों के अधिकार, परिलब्धियाँ, कर्तव्य और उत्तरदायित्व उनके अधिष्ठायी पदों के रूप में जारी रहेंगे।

(ii) उप-विनियम (2) में – स्पष्टीकरण में खंड (एफ) के बाद एवं नोट से पहले, निम्नलिखित खंड सन्निविष्ट किया जाएगा अर्थात्:-

“(जी) नवंबर, 2012 के पहले दिन से, अन्य बातों के समान होने के बावजूद, व्यावसायिक वेतन की मात्रा निम्नानुसार संशोधित हो जाएगी :

सारणी

(1)	(2)
जो इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की जूनियर एसोसिएट या इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की सर्टिफाइड एसोसिएट पार्ट -I पास कर चुके हैं	रु. 670 प्रति माह, अधिकतम स्केल तक पहुँचने के एक वर्ष बाद
जो इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट के दोनों पार्ट पास कर चुके हैं	(i) रु. 670 प्रति माह, अधिकतम स्केल तक पहुँचने के एक वर्ष बाद (ii) रु. 1680 प्रति माह अधिकतम स्केल तक पहुँचने के दो वर्ष बाद:

बशर्ते कि, वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के बाद, इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का जूनियर एसोसिएट या इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का सर्टिफाइड एसोसिएट (एक या दोनों भाग) की योग्यता रखने वाले अधिकारी को सर्टिफाइड एसोसिएट प्राप्त करने की तारीख से, व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त जारी की जाएगी और व्यावसायिक योग्यता वेतन के बाद की किस्त, पहली किस्त जारी होने की तारीख के आधार पर जारी होगी”

(iii) उप-विनियम (3) में खंड (ई) के बाद और नोट से पहले, निम्न खंड, को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

“(एफ) 1 नवंबर 2012 को और उसके बाद से अन्य मदें समान होने के कारण, मकान किराया भत्ता के साथ स्थायी वैयक्तिक वेतन निम्न दरों पर दिया जाएगा और सेवा की पूरी अवधि के लिए यही रहेगा :

सारणी

वेतन वृद्धि की राशि (रु)	01.11.2012 को वेतन वृद्धि घटक पर महंगाई भत्ता (रु)	देय कुल स्थायी व्यक्तिगत वेतन, जहां बैंक द्वारा आवास की सुविधा प्रदान की जाती है (रु)
(1)	(2)	(3)
1310	143	1453
1460	159	1619
1650	180	1830
1800	196	1996
1960	214	2174
2120	231	2351

नोट :

(i) खंड (बी), (सी), (डी), (ई) या (एफ) की सारणी (3) के अंतर्गत दर्शाये गए स्थायी व्यक्तिगत भत्ता या स्थायी व्यक्तिगत वेतन का भुगतान उन अधिकारियों को किया जाएगा, जिन्हें बैंक द्वारा आवास प्रदान किया जाता है।

(ii) जब विनियम 4 के उप-विनियम (2), (3), (4), (5) या (6) में विनिर्दिष्ट वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि दी जा रही हो, तो अधिकारियों को स्थायी व्यक्तिगत भत्ता या स्थायी व्यक्तिगत वेतन के लिए मकान किराया भत्ता के लिए पात्र राशि खंड (एफ) के तहत दी गई सारणी में कॉलम (1) और (2) में निर्दिष्ट कुल राशि और संबंधित अधिकारी को दिया जाने वाला मकान किराया भत्ता होगा।

(iii) केवल वे अधिकारी जो 01 नवम्बर, 1993 को या से पहले से बैंक की सेवा में हैं, नियुक्त स्केल की अधिकता तक पहुँचने के 01 साल के उपरांत वे स्थायी वैयक्तिक वेतन के पात्र होंगे।

(iv) 1 नवंबर, 1999 को तथा उसके बाद से स्थायी वैयक्तिक वेतन जारी करने की वजह से उप-विनियम (2) के अधीन स्पष्टीकरण (सी) के अनुसार व्यावसायिक योग्यता भत्ता जारी करने की अवधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा :

बशर्ते कि जहाँ व्यावसायिक योग्यता भत्ते की कोई किश्त जो पूर्व के प्रावधानों की वजह से एक साल के लिए आगे बढ़ाई गई है और 1 नवंबर, 1999 को या उसके बाद जारी करने के लिए नियत की गई है, वह अधिकारी को इस तिथि को तथा इस तिथि से जारी की जाएगी और व्यावसायिक योग्यता भत्ते की दूसरी किश्त, यदि कोई हो तो, 1 नवंबर, 2000 को जारी की जाएगी।

(v) स्थायी वैयक्तिक भत्ता या स्थायी वैयक्तिक वेतन की वेतनवृद्धि घटक को सेवा निवर्तन लाभ के लिए गिना जाएगा।

(vi) अधिकारी जिन्होंने उपर्युक्त शर्त (ए) के अनुसार यह अग्रिम वेतनवृद्धि अर्जित की है, वे वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के एक वर्ष के बाद ऊपर (बी), (सी), (डी), (ई) या (एफ) में बताए गए के अनुसार स्थायी वैयक्तिक भत्ते/स्थायी वैयक्तिक वेतन की मात्रा आहरित करेंगे।

(जी) 31 मार्च 2020 को और उसके बाद से अन्य मदें समान होने के कारण, उच्च प्रबंधन वेतनमान VIII में मुख्य महाप्रबंधक के पद हेतु मकान किराया भत्ता के साथ स्थायी वैयक्तिक वेतन, यदि कोई है, निम्न दरों पर दिया जाएगा और सेवा की पूरी अवधि के लिए यही रहेगा :

सारणी

वेतन वृद्धि की राशि (रु.)	वेतन वृद्धि घटक पर महंगाई भत्ता (रु.)	देय कुल स्थायी व्यक्तिगत वेतन, जहां बैंक द्वारा आवास की सुविधा प्रदान की जाती है (रु.)
(1)	(2)	(3)
2800	305	3105).

5. विनियम 7 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"7. वर्गीकरण:- (1) 31 मार्च 2020 को और उसके बाद से और विनियम 6 के प्रावधानों के अधीन, बैंक में अधिकारियों के विभिन्न पदों का वर्गीकरण इस प्रकार होगा :

सारणी

पदनाम	ग्रेड या स्केल जिसमें पदस्थापित होंगे
मुख्य महाप्रबंधक	उच्च कार्यपालक ग्रेड स्केल -VIII
महाप्रबंधक	उच्च कार्यपालक ग्रेड स्केल -VII
उप महाप्रबंधक	उच्च कार्यपालक ग्रेड स्केल -VI
सहायक महाप्रबंधक	वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल -V
मुख्य प्रबंधक	वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल -IV
वरिष्ठ प्रबंधक	मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल -III
प्रबंधक	मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल -II
अधिकारी या उप प्रबंधक	कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल -I

(2) उपर्युक्त संवर्गीकरण से यदि कोई विसंगति या कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसे ऐसी समिति जिसमें एमडी एवं सीईओ या केंद्रीय सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु नियुक्त अन्य व्यक्ति शामिल होंगे, को इसके निर्णय हेतु संदर्भित किया जाएगा।

6. उक्त विनियमों के विनियम 21 में उप-विनियम (5) के उपरान्त, निम्न विनियम, को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-
- "(6) 01 नवंबर, 2012 को और उसके बाद से, अखिल भारतीय औसत कामगार श्रेणी उपभोक्ता मूल्य सूची (सामान्य) आधार 4440 अंकों से प्रत्येक 4 अंकों की बढ़ोतरी-कमी के लिए $1960 = 100$ आधार पर वेतन का 0.10% महंगाई भत्ता देय होगा.
- स्पष्टीकरण- इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए:-
- (ए) महंगाई भत्ते के प्रयोजन के लिए "वेतन" से आशय मूल वेतन है और इसमें गतिरोध वेतन वृद्धियां शामिल हैं
- (बी) विनियम 5 के उप-विनियम 2 के स्पष्टीकरणों (सी), (डी), (ई), (एफ) तथा (जी) के अनुसार, महंगाई भत्ते के लिए व्यावसायिक योग्यता भत्ता या व्यावसायिक योग्यता वेतन को लिया जाएगा.
7. उपर्युक्त विनियमों के विनियम 22 में-
- (i) उप-विनियम (1) के लिए निम्न उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "(1) 01 नवंबर, 2012 को और उसके बाद-
- (ए) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की गई है तो उससे वेतनमान के प्रथम चरण के मूल वेतन की 0.75 प्रतिशत या आवास के लिए मानक किराया, इनमें से जो भी कम हो, के समतुल्य राशि वसूल की जाएगी;
- (बी) यदि अधिकारी को बैंक द्वारा मकान नहीं दिया गया है, तो वह निम्नवत सारणी में दर्शाई गई दरों के अनुसार मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा:-

सारणी

कार्यस्थल	मकान किराया भत्ता
(1)	(2)
(i) प्रमुख "ए" वर्ग के नगर तथा समूह ए के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 9.0%
(ii) क्षेत्र I में अन्य स्थान तथा समूह 'बी' के परियोजना क्षेत्र केन्द्र और गोवा राज्य	वेतन का 8.0%
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 7.0%

परंतु यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम चरण के 0.75 प्रतिशत से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया या उपरिवर्णित कॉलम (2) के अनुसार मकान किराए भत्ते का 150 प्रतिशत जो भी कम हो, होगा.

नोट: अधिकारी के स्वामित्व वाले आवास की लागत से संबद्ध आवास किराए भत्ते का दावा अभी तक की तरह 150 प्रतिशत तक सीमित रहेगा.;

(ii) उप-विनियम (2) हटा दिया जाएगा."

8. उक्त विनियमों के विनियम 23 में-
- (ए) उप विनियम (1), (2), (3), (4) और (5) हेतु, निम्नलिखित उप- विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "(1) दिनांक 01 नवंबर, 2012 को और उसके बाद यदि कोई अधिकारी निम्नलिखित सारणी के कॉलम (1) में उल्लिखित स्थान पर कार्यरत है तो वह कॉलम (2) में उल्लिखित दर से नगर प्रतिकर भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा:-

सारणी

स्थान	दर
(1)	(2)
(i) क्षेत्र I के स्थान और गोवा राज्य	मूल वेतन का 4 प्रतिशत अधिकतम रु.870/- प्रतिमाह
(ii) पांच लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान और राज्यों की राजधानियाँ तथा चंडीगढ़, पॉडिचेरी और पोर्ट ब्लेयर.	मूल वेतन का 3 प्रतिशत अधिकतम रु.600/- प्रतिमाह

(2) नवंबर 2012 के प्रथम दिवस को और से, विशेष क्षेत्र भत्तों की दर इन विनियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी.

(3) नवंबर 2012 के प्रथम दिवस को और से, यदि एक अधिकारी समूह 'ए' या समूह 'बी' में आने वाले विनिर्दिष्ट प्रोजेक्ट क्षेत्र में सेवाएं प्रदान कर रहा है, तो वह विनिर्दिष्ट प्रोजेक्ट क्षेत्र के लिए समूह 'ए' या समूह 'बी' क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार प्रति माह क्रमशः रुपए 400/- या रुपए 350/- की दर से प्रोजेक्ट क्षेत्र भत्ता हेतु पात्र होंगे।

(4) 01 जून, 2015 को और उसके बाद, यदि किसी अधिकारी को शैक्षिक वर्ष के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है, और यदि उसके एक या एक से अधिक बच्चे पूर्ववर्ती स्थान में विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं तो जिस तारीख को अधिकारी नई जगह पर रिपोर्ट करता है, उस तारीख से वह शैक्षिक वर्ष के अंत तक, सभी बच्चों के लिए रु.1100/- प्रति माह, मध्य शैक्षिक वर्ष स्थानांतरण भत्ते का पात्र होगा, परंतु यदि उसके सभी बच्चे पूर्ववर्ती स्थान में अध्ययन करना बंद कर देते हैं तो यह भत्ता मिलना बंद हो जाएगा।

(5) 01 जून, 2015 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह प्रतिनियुक्ति के पद पर देय उन परिलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अपना विकल्प दे सकता है। विकल्पतः वह अपने वेतन के अतिरिक्त 7.75 प्रतिशत अधिकतम रु.4000/- प्रति माह के अधीन प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते ले सकता है जो उसे उसी स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने की स्थिति में मिलता है :

यह भी कि यदि उसे प्रतिनियुक्ति से पूर्व उसकी तैनाती के स्थान पर ही स्थित किसी संस्था में प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो उसे उसके वेतन का 4 प्रतिशत अधिकतम रु.2000/- प्रति माह के अधीन प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा :

परंतु यदि किसी अधिकारी को बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसे उसके वेतन का 4% अधिकतम रु.2000/- के अधीन प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा."

(बी) उप-विनियम (8) हेतु, निम्नलिखित उप-विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(8) 01 नवंबर, 2012 से या उसके बाद से यदि किसी दिन के दौरान उसके कार्य के घण्टों को कम से कम दो घंटों के अंतराल में विभाजित किया जाता है तो अधिकारी रु.200/- प्रति माह के विभाजित छूटी भत्ता हेतु पात्र होगा.;"

(सी) उप-विनियम (10) में,

(ए) "नवंबर 2007 का प्रथम दिवस" आंकड़े, अक्षरों एवं शब्दों के लिए, "नवंबर, 2012 का प्रथम दिवस "आंकड़े, अक्षर एवं शब्द के रूप में प्रतिस्थापित होगा;

(बी) सारणी हेतु, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित होगी, अर्थात्:-

"सारणी

स्थान	दर
(1)	(2)
(i) 1000 मीटर और उससे अधिक परंतु 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान और मर्करा नगर	वेतन का 2% अधिकतम रु 750/- के अधीन
(ii) 1500 मीटर और उससे अधिक परंतु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान और मर्करा नगर	वेतन का 2.5% अधिकतम रु 1000/- के अधीन
(iii) 3000 मीटर और उससे ऊंचाई वाले स्थान पर	वेतन का 5% अधिकतम रु 2000/- के अधीन."

9. उक्त विनियमों के विनियम 24 में,-

(i) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) 1 नवंबर, 2012 को उसके बाद से एक अधिकारी स्वयं तथा परिवार के लिए निम्नवत सारणी के अनुसार चिकित्सा व्यय प्राप्त करने का पात्र होगा जिसके लिए अधिकारी को अपनी ओर से ही प्रमाण-पत्र देना होगा कि उसने यह व्यय किया है और दावा की गई राशि के समर्थन में उसे खर्च का विवरण देना होगा:-

सारणी

ग्रेड	अधिकतम वार्षिक प्रतिपूर्ति सीमा
(1)	(2)
कनिष्ठ प्रबंधन एवं मध्यम प्रबंधन श्रेणी	रु 8000/- प्रति वर्ष या व्यय की गई राशि जो भी कम हो
वरिष्ठ प्रबंधन एवं शीर्ष प्रबंधन श्रेणी	रु 9050/- प्रति वर्ष या व्यय की गई राशि जो भी कम हो

- नोट: (i) अनुपयुक्त चिकित्सा सहायता राशि को अधिकारी संचित कर सकता है परंतु संचित राशि किसी भी समय उपर्युक्त अधिकतम राशि के तीन गुने से अधिक न होगा; या
- (ii) वर्ष 2012 के लिए चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति को दो महीने अर्थात् नवंबर 2012 एवं दिसंबर 2012 के लिए समानुपातिक रूप से बढ़ा दिया जाएगा।

(1ए) बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अनुसार, एक अधिकारी स्वयं तथा अपने परिवार के लिए चिकित्सा बीमा सुविधा के लिए पात्र होगा।

10. उक्त विनियमों के विनियम 25 में, उप-विनियम (2) हेतु, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) उप-विनियम (1) में निहित किसी बात के बावजूद (1), यद्यपि बैंक चाहे तो अधिकारी को आवास उपलब्ध करा सकता है जिसके लिए अधिकारी दिनांक 01 नवंबर, 2012 को और उसके बाद से अपने वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन के 0.75 प्रतिशत के बराबर की राशि या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, भुगतान करेगा :

परंतु यदि ऐसे आवास पर फर्नीचर भी उपलब्ध कराया गया हो तो अधिकारी से उसके वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन के 0.15% के बराबर अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी:

परंतु यदि बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराया जाता है तो बिजली, पानी, गैस तथा संरक्षण प्रभार अधिकारी को देना पड़ेगा।

11. उक्त विनियमों के विनियम 33 में, उप-विनियम (4) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4) 01 जून, 2015 को या से अर्जित अवकाश के आवेदन के नामजूर होने के अतिरिक्त आवेदित अवकाश 270 दिन से अधिक संचित नहीं की जा सकेगी:

बशर्ते कि अर्जित अवकाश का नकदीकरण अधिकतम 240 दिनों तक प्रतिबंधित रहेगा:

बशर्ते कि अर्जित अवकाश लेने का इच्छुक अधिकारी सामान्यतः ऐसा अवकाश लेने के पहले आशय की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व देगा।

12. उक्त विनियमों के विनियम 34 में, उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4) 01 जून, 2015 को तथा से, किडनी या अंग दान करने हेतु एक अधिकारी को पूरे सेवाकाल के दौरान एक बार 30 दिनों का विशेष बीमारी अवकाश मंजूर किया जा सकेगा।

13. उक्त विनियमों के विनियम 36 में, उप विनियम (2) एवं (3) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2) दिनांक 25 मई, 2015 से प्रभावी, संतानहीन महिला कर्मचारी को भी एक साल से कम उम्र के बच्चे को, विधिक रूप से गोद लेने के लिए सेवा के दौरान एक बार अवकाश दिया जा सकता है जिसकी अधिकतम अवधि निम्नलिखित शर्तों पर छह महीने होगी:-

(i) अवकाश एक ही बच्चे को गोद लेने के लिए प्रदान किया जाएगा;

(ii) बच्चे को सही विधिक प्रक्रिया के जरिये गोद लेना चाहिए और ऐसा अवकाश मंजूर करने के लिए कर्मचारी को बैंक के समक्ष दत्तक-ग्रहण विलेख प्रस्तुत करना चाहिए;

(iii) ऐसे मामलों में उन जैविक माओं के लिए भी अवकाश उपलब्ध होगा जहां बच्चे का जन्म सरोगेसी के जरिये हुआ है, और

(iv) इस अवकाश का उपभोग सम्पूर्ण सेवा काल के दौरान बारह माह की समग्र पात्रता के अंतर्गत किया जाएगा।

(3) दिनांक 25 मई, 2015 से प्रभावी, 12 माह की कुल सीमा के अंदर बच्चेदानी हटाने के मामले में अधिकतम साठ दिन का अवकाश भी स्वीकृत किया जा सकता है।

(4) मातृत्व अवकाश जो स्थायी वेतन पर होगा, किसी भी महिला अधिकारी को एक अवसर पर छह माह से अनधिक समय एवं उसकी सेवा की सम्पूर्ण अवधि में बारह माह से अधिक नहीं होगा :

बशर्ते कि 12 माह की समग्र अवधि के अंदर, मिसकैरेज, गर्भपात या गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति के मामले में भी अवकाश मंजूर किया जा सकता है।

(5) 01 जून, 2015 से, पुरुष अधिकारी 02 जीवित बच्चों हेतु उसकी पत्नी की प्रसव अवस्था के दौरान 15 दिनों के लिए पितृत्व अवकाश की मंजूरी के लिए पात्र होगा, यह अवकाश आकस्मिक अवकाश के अलावा किसी भी अवकाश के साथ लिया जा सकता है:

बशर्ते कि अवकाश हेतु आवेदन बच्चे की डिलिवरी की तिथि से 15 दिनों से पूर्व या 06 माह तक किया जाएगा।

14. उक्त विनियमों के विनियम 38 के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(38) अवकाश का रद्द होना-नीचे उल्लिखित को छोड़कर एक अधिकारी के नाम पर जमा सभी छुट्टियाँ उनके इस्तीफे, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, दायित्व मुक्त, पदच्युति अथवा सेवा समाप्ति पर रद्द हो जायेंगी :

परंतु जहाँ कोई अधिकारी बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होता है वह किसी भी अवधि की परिलब्धियों की समतुल्य राशि जो कि उसके द्वारा जमा अर्जित अवकाश के 240 दिनों से अधिक न हो के लिए पात्र होंगे :

परंतु जहां किसी अधिकारी को दंड स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है, उनके द्वारा संचित अधिकतम 240 दिनों के अर्जित अवकाश हेतु किसी अवधि की परिलब्धियों की राशि के भुगतान हेतु वह पात्र होंगे:

परंतु जहाँ किसी अधिकारी की सेवकाल में मृत्यु हो जाती है वहां उनकी मृत्यु के दिनांक पर उनके नाम पर जमा अर्जित अवकाश में से 240 दिनों तक की अवधि के लिए परिलब्धियों की समतुल्य राशि उनके विधिक प्रतिनिधियों को प्रदान की जाएगी :

परंतु जहां कोई अधिकारी 1 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद विनियम 20 के उप विनियम (2) के तहत नियत सूचना देने के पश्चात् अपनी सेवा से त्यागपत्र देता है तो उसके संचित अर्जित अवकाश के आधे हिस्से, अधिकतम 120 दिनों तक के लिए परिलब्धियों की समतुल्य राशि प्रदान की जा सकती है."

15. उक्त विनियमों के नियम 41 में,—

(i) उप-नियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) 01 नवंबर, 2012 को और उसके बाद एक अधिकारी छट्टी पर यात्रा करने में निम्नलिखित के लिए पात्र होगा:—

(ए) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी का अधिकारी रेल की प्रथम श्रेणी या 2-टियर एसी स्लीपर में यात्रा करने के लिए पात्र होगा :

बशर्ते कि कारोबार की अनिवार्यताओं या लोकहित को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से वह विमान (इकोनॉमी श्रेणी) द्वारा यात्रा कर सकता है;

(बी) मध्यम प्रबंधन श्रेणी का अधिकारी रेल की प्रथम श्रेणी या 2-टियर एसी स्लीपर में यात्रा करने के लिए पात्र होगा :

परंतु यदि यात्रा की दूरी 1000 कि.मी. से अधिक हो तो वह विमान (इकोनॉमी श्रेणी) द्वारा यात्रा कर सकता है;

परंतु कारोबार की अनिवार्यताओं या लोकहित को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से, वह इससे कम की दूरी की यात्रा भी इकोनॉमी श्रेणी में विमान द्वारा कर सकता है—

(सी) वरिष्ठ प्रबंधन या उच्च कार्यपालक श्रेणी का अधिकारी रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या विमान (इकोनॉमी श्रेणी) द्वारा यात्रा कर सकता है—

(डी) वरिष्ठ प्रबंधन या उच्च कार्यपालक श्रेणी का अधिकारी, ऐसे स्थानों के बीच, जो विमान सेवा या रेल-सेवा से जुड़े हुए नहीं हैं, कार द्वारा यात्रा कर सकता है बशर्ते कि यात्रा की यह दूरी 500 कि.मी. से अधिक न हो;

बशर्ते कि उक्त दोनों स्थानों के बीच की अधिकांश दूरी विमान या रेल यात्रा द्वारा तय की जा सकती हो तो सामान्यतः केवल शेष दूरी कार द्वारा तय की जानी चाहिए—

(ई) सक्षम प्राधिकारी, कारोबार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, किसी भी अधिकारी को उसकी गाड़ी से यात्रा करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है;

(एफ) किसी भी ग्रेड या स्केल का अधिकारी, उन स्थानों के बीच जल परिवहन द्वारा डीलक्स केबिन श्रेणी में यात्रा कर सकेगा जो स्थान सड़क, हवाई मार्ग या रेल से जुड़े नहीं हैं;

(ii) उप-नियम (4) में, खंड (ए) और (बी) के लिए, निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(ए) 1 जून 2015 को और इसके बाद से नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में उल्लिखित ग्रेड या वेतनमान का अधिकारी कॉलम (2) में निर्दिष्ट तत्संबंधी दरों पर दैनिक विराम भत्ते का पात्र होगा:—

सारणी

अधिकारियों के ग्रेड/वेतनमान	मेट्रो (रु.)	प्रमुख 'ए' वर्ग के नगर (रु.)	क्षेत्र-1 (रु.)	अन्य स्थान (रु.)
(1)	(2)			
वेतनमान VI व उससे अधिक के अधिकारी	1800	1300	1100	950
वेतनमान IV व V के अधिकारी	1500	1300	1100	950
वेतनमान I/II व III के अधिकारी	1300	1100	950	800

परंतु यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम किंतु चार घंटे से अधिक है तो विराम भत्ता उपयुक्त दरों से आधी दरों पर देय होगा.

स्पष्टीकरण— विराम भत्ते की गणना के प्रयोजन के लिए प्रतिदिन से 24 घंटे की प्रत्येक अवधि या उसका पश्चातवर्ती भाग अभिप्रेत है, जिसकी गणना वायुयान द्वारा यात्रा की स्थिति में, प्रस्थान के लिए रिपोर्ट के समय से और अन्य स्थितियों में स्थान के निर्धारित समय से पहुँचने के वास्तविक समय तक की होगी. जहाँ अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटे से कम है, वहाँ प्रतिदिन से कम से कम 8 घंटे की अवधि अभिप्रेत है.

(बी) 31 मार्च 2020 को और उसके बाद से निम्नलिखित तालिका के कॉलम (1) में निर्धारित ग्रेड या स्केल में, एक अधिकारी को भारतीय पर्यटन विकास निगम के कॉलम (2) के अनुरूप स्टार श्रेणी के होटलों में वास्तविक होटल खर्च की प्रतिपूर्ति की जा सकती है, लेकिन यह सिंगल कमरे में ठहरने तक सीमित होगा:

सारणी

अधिकारियों के ग्रेड / वेतनमान	ठहरने की पात्रता
(1)	(2)
वेतनमान VI, VII व VIII	4 स्टार होटल
वेतनमान IV व V	3 स्टार होटल
वेतनमान II व III	2 स्टार होटल (अवातानुकूलित)
वेतनमान I	1 स्टार होटल (अवातानुकूलित)

बशर्ते कि बोर्ड, केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऊपर दी गई सीमा से अधिक सीमा की प्रतिपूर्ति के लिये निर्दिष्ट कर सकता है."

16. उक्त विनियमों के नियम 42 में उप-नियम (3) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

"(3) 01 जून, 2015 को और उसके बाद एक अधिकारी सामान की पैकिंग, स्थानीय परिवहन, उसके बीमा आदि के लिए निम्नवत सारणी के अनुसार एकमुश्त राशि पाने का पात्र होगा:-

सारणी

ग्रेड / वेतनमान	राशि
(1)	(2)
शीर्ष कार्यपालक और वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड (वेतनमान IV एवम ऊपर के अधिकारी)	रु. 20,000
मध्यम प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड (वेतनमान III तक के अधिकारी)	रु. 15,000

17. उक्त नियमों के नियम 44 में, उप-नियम (3) के लिए निम्नलिखित उप-नियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) चार वर्षों के प्रत्येक खण्ड के दौरान अधिकारी दो वर्षों के प्रत्येक खण्ड में एक बार अपने गृहनगर की यात्रा के लिए अवकाश यात्रा रियायत पाने का पात्र होगा:

परंतु यह और भी कि विकल्पतः वह दो वर्षों के एक खण्ड में अपने गृहनगर और दूसरे खण्ड में भारत में किसी भी स्थान की सबसे कम दूरी के मार्ग से यात्रा कर सकता है:

परंतु यह और कि 1 जून, 2015 से, वैकल्पिक रूप से, एक अधिकारी चार वर्षों अथवा दो वर्षों के ब्लॉक, जैसा भी मामला हो अपनी अवकाश यात्रा रियायत को छोड़ने और नकदीकरण (गृह नगर में यात्रा के अतिरिक्त) के विकल्प का इस्तेमाल कर सकता है जिसके लिए वह स्वयं को पात्र रेल की श्रेणी में जेएमजी वेतनमान I के अधिकारी, एमएमजी वेतनमान II और III के अधिकारियों के लिए 4500 कि.मी की दूरी (एकतरफ) और वेतनमान IV एवं ऊपर के अधिकारी 5500 कि.मी की दूरी (एकतरफ), पात्र किराये के समान राशि प्राप्त करेंगे:

परंतु यह और कि 1 जून, 2015 से, कोई अधिकारी अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए केवल एक ब्लॉक अथवा अवधि जिसमें ऐसा नकदीकरण प्राप्त किया गया है, के लिए यात्रा अवकाश रियायत के नकदीकरण का विकल्प चुन सकता है. यात्रा अवकाश रियायत का उपयोग करते समय अर्जित अवकाश का नकदीकरण भी यात्रा अवकाश भत्ते के नकदीकरण के साथ प्राप्त कर सकते हैं.

(3ए) अवकाश यात्रा रियायत सुविधा के लिए अधिकारी उसी साधन और श्रेणी का उपयोग कर सकता है जिससे कि वह स्थानांतरण पर यात्रा करने का पात्र है और अधिकारी द्वारा अवकाश यात्रा रियायत के उपयोग की अन्य निबंधन एवं शर्तें निदेशक-मण्डल (बोर्ड) द्वारा समय-समय पर विनिर्धारित निबंधन एवं शर्तें होंगी:

परंतु 1 मई, 2010 से कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I का अधिकारी विमान में इकोनामी श्रेणी के निम्नतम किराये में यात्रा करने का पात्र होगा, जिसके लिए रेल में यात्रा की दूरी के लिए वास्तविक किराया या वातानुकूलित प्रथम श्रेणी हेतु लागू किराया जो भी कम हो प्रदान किया जाएगा. समान नियम मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II और मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III के अधिकारियों के लिए भी अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग करने पर लागू होंगे, जहां दूरी 1000 कि.मी से कम हो".

18. उक्त विनियमों की अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“अनुसूची

[विनियम 23(2) देखें]

एक अधिकारी, 1 नवंबर 2012 से प्रभावी नीचे दी गयी तालिका के अनुसार विशेष क्षेत्र भत्ता पाने का तब तक पात्र होगा, जब तक कि इसे पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वापस न ले लिया जाए या संशोधित न कर दिया जाए:-

सारणी

क्र.	क्षेत्र	भत्ता (रु में)	
		रु 24000 से कम वेतन	रु 24000 से अधिक वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मिजोरम (क) चिमपतुईपुई जिला और लुंगलेई जिले के लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर दूर के क्षेत्र. (ख) लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर से दूर के क्षेत्रों को छोड़कर पूरा लुंगलेई जिला. (ग) पूरा आईजोल जिला	2000 1600 1200	2600 2100 1500
2	नागालैण्ड	1600	2100
3	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (ए) उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, नीकोबार और नारकोंडम द्वीप (बी) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	2000 1600	2600 2100
4	सिक्किम	2000	2600
5	लक्षद्वीप द्वीप समूह	2000	2600
6	असम	320	400
7	मेघालय	320	400
8	त्रिपुरा (ए) त्रिपुरा के कठिन क्षेत्र (बी) कठिन क्षेत्रों को छोड़कर पूरे त्रिपुरा राज्य में	1600 1200	2100 1500
9	मणिपुर	1200	1500
10	अरुणाचल प्रदेश (ए) अरुणाचल प्रदेश के कठिन क्षेत्र (बी) कठिन क्षेत्रों को छोड़कर पूरे अरुणाचल प्रदेश में	2000 1600	2600 2100
11	जम्मू एवं कश्मीर (ए) कठुआ जिला: नियाबत बानी, लोही, मल्हार और मछोडी (बी) उधमपुर जिला : i) भाग 2 (बी) में शामिल के अलावा डूडू बसंतगढ़, लैंडर भामाग इलाका ii) कंबन की ओर से गोयल तक का क्षेत्र और मोहरे तहसील में कियासी की ओर से अरनास तक का क्षेत्र (सी) डोडा जिला : पैडर का इलाका और किशतवाड तहसील में नियाबत नौगांव (डी) लेह जिला : जिले का संपूर्ण क्षेत्र (ई) बारामुला जिले i) पूरा गुरेज – निराबात, तंगदार उप-मंडल और केरन इलाका ii) मच्छिल (एफ) पुंछ और राजौरी जिला: पुंछ और राजौरी जिले के क्षेत्र, जिनमें पुंछ और राजौरी शहर और सुंदरबनी और इन दोनों जिलों के अन्य शहरी क्षेत्र शामिल नहीं हैं	2000 2000 1600 2000 2000 2000 2000 1600 1200	2600 2600 2100 2600 2600 2600 2600 2100 1500

	(जी) उपरोक्त (ए) से (एफ) तक में शामिल नहीं किए गए क्षेत्र, परंतु वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 किमी. के दायरे में आने वाले क्षेत्र या ऐसे स्थान, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने स्टाफ सदस्यों के लिए समय-समय पर बार्डर भत्ता हेतु पात्र घोषित किया जाता है	1200	1500
12	हिमाचल प्रदेश 1. चंबा जिला (ए) पांगी तहसील, भरमौर तहसील, पंचायत : बदगाँव, बाजोल, देओल कुगती, नयागाम और दुंडा, गाँव: जगत ग्राम पंचायत का घाटू, चौहाटा ग्राम पंचायत का कनरसी (बी) भरमौर तहसील, उपर्युक्त मद (ए) में शामिल किए गए पंचायतों और गांवों को छोड़कर (सी) भटीयट तहसील में झंडरू पंचायत, चुरा तहसील डलहौजी टाउन (बानीखेत मुख्य सहित)	2000 1600 1200	2600 2100 1500
	2. किन्नौर जिला : (i) असरंग, चितकुल और हंगो कुनो / चारंग पंचायत, छोटा खंबा की ग्राम पंचायतों सहित 15/20 क्षेत्र नाथपा और रूपी, पूह उप-मंडल, ऊपर निर्दिष्ट पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर. (ii) उपरोक्त (i) में शामिल क्षेत्रों के अलावा पूरा जिला	2000 1600	2600 2100
	3. कुल्लू जिला : (i) खरगा, कुशवर और सारगा की ग्राम पंचायतों सहित निरमंड तहसील के 15/20 क्षेत्र. (ii) बाहरी-सरज (निरमंड तहसील में जकत- खाना और बरो के गांवों को छोड़कर) तथा बाहरी सेराज क्षेत्र और पंडराबिस के परगना को छोड़कर लेकिन जकत-खाना और निरमंड तहसील के बरो गांवों सहित पूरा जिला).	2000 1200	2600 1500
	4. लाहौल एवं स्पीति जिला : लाहौल एवं स्पीति के संपूर्ण क्षेत्र	2000	2600
	5. शिमला जिला : (i) कूट, लबाना-सदन, सरपारा और चाडी-ब्रांदा की पंचायतों सहित रामपुर तहसील के 15/20 क्षेत्र. (ii) डोरा- कवार तहसील, रामपुर में दरकाली की ग्राम पंचायत कशापठ तहसील तथा सराहन परगना के मुनीश, घोरी चायबीस. (iii) सराहन परगना के चौपाल तहसील तथा घोरीस, पंजगाँव, पदसनऊ, नौबीस और तीनकोटि, तकलेश क्षेत्र, परगना का देवथी ग्रामपंचायत, बरबिस परगना, रामपुर तहसील के रामपुर परगना का कस्बा रामपुर और घोरीनोग, शिमला टाउन और उसके उपनगर (ढल्ली, जतोग, कसूम्टी, मशोबरा, तारादेवी और तुतु).	2000 1600 1200	2600 2100 1500
	6. कांगड़ा जिला : (i) बड़ा भंगाल और छोटा भंगाल के क्षेत्र (ii) कांगड़ा जिले के धर्मशाला शहर और नगर निगम सीमा के बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय है, लेकिन धर्मशाला टाउन महिला आईटीआई, दारी, यांत्रिक कार्यशाला, रामनगर, बाल कल्याण और शहर और देश योजना कार्यालयों, सकोह, लोवर सकोह में स्थित सीआरएसएफ कार्यालय, कांगड़ा दूध आपूर्ति योजना, दुगीयार, एचआरटीसी कार्यशाला, सधेर, जोनल मलेरिया कार्यालय, दारी, वन निगम कार्यालय, शामनगर, चाय फैक्ट्री, दारी, आईपीएच -उप-मंडल, दान, निपटान कार्यालय, शामनगर, हिनवा परियोजना, शामनगर. कांगड़ा जिले का पालमपुर शहर जिसमें पालमपुर का एचपीकेवीवी कैम्पस और पालमपुर नगर निगम सीमा के बाहर स्थित निम्न कार्यालय शामिल होंगे: एच पी कृषि विश्व विद्यालय कैम्पस, मवेशी विकास कार्यालय / जर्सी फार्म, बानूरी, रेशम उत्पादन कार्यालय / भारत-जर्मन कृषि कार्यशाला / एचपीपीडब्ल्यूडी प्रभाग, बुंदला विद्युत उप-मंडल, लोहना, डीपीओ निगम बुंदला, विद्युत एचईएसईई प्रभाग, घुग्गर.	1600 1200	2100 1500

	7. मंडी जिला : जोगिन्द्रनगर तहसील की छोहर घाटी, बागरा की थूंग तहसील में पंचायत, चत्री, छोटधर, गरागुशाइन, गादू, गर्यास, जंजेहली, जरयार, जोहर, कलहानी, कलवा, खोलनाल, लोथ, सिलिबागी, सोमचान, थचदार, ताची, थाना, धरमपुर ब्लॉक-बिंगा के पंचायत, कमला, सकलाना, तन्यर और तरखोला, कारसोग तहसील-बलीधर के तहसील, बागरा, गोपालपुर, खाजोल, महोग, मेहुदी, मौंज, पेखी, साइंज, सराहन और टेबन, सुंदरनगर तहसील-बोही के पंचायत, बटवारा, धन्यारा, पौराकोठी, सेरी और शोजा.	1200	1500
	8. सिरमौर जिला: बानी के पंचायत, (पछड़ तहसील), भरोग भेनेरी, पांवटा तहसील), बिरला (नाहन तहसील), डिब्बर (पछड़ तहसील) और थाना कासोगा (नाहन तहसील) और ठांसगिरी ट्रैक	1200	1500
	9. सोलन जिला: मंगल पंचायत	1200	1500
	10. हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र जो उपरोक्त (1) से (9) में शामिल नहीं हैं	320	400
13	उत्तर प्रदेश चमोली, पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी जिला के अंतर्गत क्षेत्र.	2000	2600
14	उत्तराखंड चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग एवं चम्पावत जिला के अंतर्गत क्षेत्र.	2000	2600

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इन विनियमों में दिए गए पूर्वव्यापी प्रभाव यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों को वेतन, अन्य भत्ते और लाभों से संबंधित हैं और निश्चित रूप से हितकारी विधान हैं. इसलिए, इन विनियमों के उक्त प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से इस तरह के पूर्वव्यापी आवेदन के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

एस. के. महापात्रा, क्षेत्र महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./526/19]

नोट: संशोधित विनियम भारत के राजपत्र में, भाग III के खंड 4 में प्रकाशित किये गए. निम्नलिखित अधिसूचनाओं का संदर्भ लें, यथा :-

क्र.स.	अधिसूचना क्र.	दिनांक
1	ओरएसआर/1	14.11.1987
2	ओरएसआर/2	04.06.1988
3	ओरएसआर/3	04.06.1988
4	ओरएसआर/4	30.12.1989
5	ओरएसआर/5	27.10.1990
6	ओरएसआर/6	11.01.1992
7	ओरएसआर/7	12.12.1992
8	ओरएसआर/8	27.02.1993
9	ओरएसआर/9	25.09.1993
10	ओरएसआर/10	10.09.1994
11	ओरएसआर/11	07.01.1995
12	ओरएसआर/12	07.09.1996
13	ओरएसआर/13	21.12.1996
14	ओरएसआर/14	21.12.1996
15	ओरएसआर/15	21.12.1996
16	ओरएसआर/15	06.02.1996
17	ओरएसआर/16	03.06.2000
18	ओरएसआर/16	30.12.2000

19	ओरएसआर/17	09.12.2000
20	ओरएसआर/18	29.10.2002
21	ओरएसआर/19	18.06.2003
22	ओरएसआर/20	27.01.2006
23	ओरएसआर/21	10.03.2007
24	ओरएसआर/22	25.09.2017

UNION BANK OF INDIA
(Human Resources Department)
(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 27th March, 2020

F. No. CO:ERD:1071:2020(E).—In exercise of powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Union Bank of India, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby make the following regulations further to amend the Union Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Union Bank of India (Officers') Service(Amendment) Regulations, 2020.

(2) Save as provided in these regulations, they shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of November, 2012.

2. In the Union Bank of India(Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3, for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:—

“(f) “family” means the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children), wholly dependent physically and mentally challenged brother or sister with forty per cent or more disability, widowed daughters and dependent divorced or separated daughters, sisters including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters, and parents wholly dependent on the officer and in the case of a married female officer may include her natural parents or parents-in-law, but not both.

Explanation.—“wholly dependent” shall mean such member of the family having an income not exceeding Rs.10,000 per month and where the wholly dependent family member are parents, the income of any parent or aggregate income of both the parents if exceeds Rs.10,000 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer;”.

3. In regulation 4 of the said regulations, for sub-regulation (6), the following sub-regulations shall be inserted, namely:—

“(6) With effect from the 1st November, 2012, the scales of pay specified against each grade shall be as under:

(a) Top Executive Grade

Scale VII = Rs.76520 – 2120/4 – 85000

Scale VI = Rs.68680 – 1960/4 – 76520

(b) Senior Management Grade

Scale V = Rs.59170 – 1650/2 – 62470 – 1800/2 – 66070

Scale IV = Rs.50030 – 1460/4 – 55870 – 1650/2 – 59170

(c) Middle Management Grade

Scale III = Rs.42020 – 1310/5 – 48570 – 1460/2 – 51490

Scale II = Rs.31705 – 1145/1 – 32850 – 1310/10 – 45950

(d) Junior Management Grade

Scale I = Rs.23700 – 980/7 – 30560 – 1145/2 – 32850 – 1310/7 – 42020

Explanation.—Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on 31st October, 2012 shall be fitted in the scale of pay as set out in this sub-regulation as on 1st November, 2012 on stage-to-stage basis or the corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual.

(7) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3), (4), (5) and (6) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.

(8) With effect from the 1st day of November, 2012, officers shall be paid Special Allowance as under:

Scale I–III = 7.75% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV–V = 10% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI–VII = 11% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

(9) On and from the 31st day of March, 2020, the Scale of Pay and Special Allowance for the post of Chief General Manager in Top Executive Grade shall be as under:

(A) Top Executive Grade

Scale VIII = Rs.1,03,000 – 2,700/3 – 1,11,100 – 2,800/1 – 1,13,900

(B) Special Allowance

Scale VIII = 11% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon:

Provided that nothing in this sub-regulation shall be construed as requiring the Bank to have at all times officers serving in this grade.

Note: The Special Allowance referred to in sub-regulations (8) and (9) with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, such as pension including New Pension Scheme, Provident Fund and Gratuity.”.

4. In regulation 5 of the said regulations,—

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) Subject to the provisions of sub-regulation (6) of regulation 4, on and from the 1st November, 2012, the increments shall be granted subject to the following, namely:—

- (a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (6) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
- (b) one year after reaching the maximum in their respective Scales, officers in Scale I and Scale II, shall be granted further increments including stagnation increment in the next higher Scale only as specified in clause (c) below subject to their crossing the efficiency bar;
- (c) officers in Junior Management Grade Scale I who have moved to Middle Management Grade Scale II in terms of clause (b) after reaching maximum of the higher Scale, shall be eligible for four stagnation increments for every three completed years of service of which the first two shall be Rs. 1310 each and next two, Rs. 1460 each;
- (d) officers in Middle Management Grade Scale II who have moved to Middle Management Grade Scale III in terms of clause (b) after reaching maximum of higher scale shall be eligible for three stagnation increments of Rs.1460 each for every three completed years of service and a fourth stagnation increment of Rs. 1460 two years after receipt of third stagnation increment:

Provided that officers who have completed two years or more after receipt of the third stagnation increment shall be granted the fourth stagnation increment with effect from the 1st day of May, 2015;

- (e) officers in substantive Middle Management Grade Scale III (those recruited in or promoted to Middle Management Grade Scale III) shall be eligible for three stagnation increments of Rs. 1460 each for every three completed years of service and fourth stagnation increment of Rs. 1460 to officers who have completed two years or more after releasing third stagnation increment as on 1st May, 2015 and a fifth stagnation increment of Rs. 1460 two years after receipt of fourth stagnation increment provided that the officers who have completed two years after receipt of the fourth stagnation increment shall be granted the fifth stagnation increment with effect from 1st May, 2015;
- (f) officers in Senior Management Grade Scale-IV shall be eligible for one stagnation increment of Rs. 1650 three years after reaching the maximum of scale with effect from 1st May, 2015:

Provided that such increment shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Explanation.—Grant of such increments in the next higher Scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.”;

(ii) in sub-regulation (2), in the *Explanation*, after clause (f) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:—

“(g) On and from the 1st day of November, 2012, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the Table below:

TABLE

(1)	(2)
Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers – Part I	Rs. 670 per month, one year after reaching maximum of the scale
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs. 670 per month, one year after reaching maximum of the scale (ii) Rs.1680 per month, two years after reaching maximum of the scale:

Provided that an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay”;

(iii) in sub-regulation (3), after the table under clause (e), the following shall be inserted, namely:—

“(f) On and from the 1st November, 2012, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:

TABLE

Increment component (Rs.)	Dearness Allowance as on 01.11.2012 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where Bank's accommodation is provided (Rs.)
(1)	(2)	(3)
1310	143	1453
1460	159	1619
1650	180	1830
1800	196	1996
1960	214	2174
2120	231	2351

Note:

(i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (3) of the tables in clauses (b), (c), (d), (e) and (f) of this sub-regulation shall be payable to those officer who are provided with Bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (1) and (2) of the table under clause (f) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4), (5) and (6) of regulation 4 is earned.

(iii) Only officers who were in the service of the Bank on or before 1st November, 1993 shall be eligible for Fixed Personal Pay one year after reaching the maximum scale of pay they are placed.

(iv) On and from the 1st November, 1999 there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in Explanation (c) of sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after the 1st November, 1999, it shall be released to the officer on and from that date and second installment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released on the 1st November, 2000.

(v) The increment component of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.

(vi) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) of this sub-regulation shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d), (e) or (f) above, one year after reaching the maximum of the scale.

(g) On and from the 31st day of March, 2020, other things being equal, the Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance, if any, for the post of Chief General Manager in Top Executive Grade Scale-VIII shall be at the rates given in the table below and shall remain frozen for the entire period of service:

TABLE

Increment component (Rs.)	Dearness Allowance on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(1)	(2)	(3)
2800	305	3105

5. For regulation 7, the following regulation shall be substituted, namely:—

“7. Categorisation.— (1) On and from the 31st day of March, 2020, and subject to the provisions of regulation 6, the various posts of officers in the Bank shall be categorized as specified in the table below:

TABLE

POSTS	GRADE or SCALE IN WHICH PLACED
Chief General Manager	Top Executive Grade Scale-VIII
General Manager	Top Executive Grade Scale-VII
Deputy General Manager	Top Executive Grade Scale-VI
Assistant General Manager	Senior Management Grade Scale-V
Chief Manager	Senior Management Grade Scale-IV
Senior Manager	Middle Management Grade Scale-III
Manager	Middle Management Grade Scale-II
Asstt. Manager	Junior Management Grade Scale-I

(2) If any difficulty or anomaly arises out of the above categorization, the same shall be referred to a Committee consisting of the Managing Director and Chief Executive Officer and such other person or persons as may be appointed by the Central Government for this purpose, for its decision.”.

6. In regulation 21 of the said regulations, after sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(6) On and from the 1st day of November, 2012, Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 4440 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.10% of pay.

Explanation.— For the purposes of this sub-regulation,—

- “pay” for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments plus Special Allowance;
- Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in clauses (c), (d), (e), (f) and (g) to the explanation in sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for Dearness Allowance.”.

7. In regulation 22 of the said regulations,—

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) On and from the 1st day of November, 2012,—

- where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 0.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
- where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:—

TABLE

Place of work	House Rent Allowance
(1)	(2)
(i) Major “A” Class Cities and Project Area Centres in Group A	9.0% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B and State of Goa	8.0% of Pay
(iii) Other places	7.0% of Pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 0.75 per cent of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) of the above Table.

Note: The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent of the House Rent Allowance as hitherto.”;

(ii) sub-regulation (2) shall be omitted.”.

8. In regulation 23 of the said regulations,—

(A) for sub-regulations (1), (2), (3), (4) and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

“(1) On and from the 1st day of November, 2012, if an officer is serving in a place mentioned in column (1) of the table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in column (2) thereof against that place shall be payable:—

TABLE

Places	Rate
(1)	(2)
(i) Places in Area I and in the State of Goa	4% of Basic Pay subject to a maximum of Rs.870 per month
(ii) Places with population of five lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair	3% of Basic Pay subject to a maximum of Rs.600 per month.

- (2) On and from the 1st day of November, 2012, the rates of special areas allowances shall be as specified in the Schedule to these regulations.
- (3) On and from the 1st day of November, 2012, if an officer is serving in an area specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.400 per month or Rs.350 per month according to the classification of area as Group A or Group B respectively.
- (4) On and from the 1st day of June, 2015, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs. 1100 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.
- (5) On and from the 1st day of June, 2015, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent of pay subject to a maximum of Rs.4000 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent of his pay subject to a maximum of Rs.2000 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent of his pay subject to a maximum of Rs.2000 per month.”;

(B) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(8) On and from the 1st day of November 2012, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.200 per month.”;

(C) in sub-regulation (10),—

(a) for the figures, letters and words “1st day of November 2007”, the figures, letters and words “1st day of November, 2012” shall be substituted;

(b) for the Table, the following table shall be substituted, namely:—

“TABLE

Place	Rate
(1)	(2)
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs. 750 per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2.5% of pay subject to a maximum of Rs.1000 per month
(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.2000 per month”.

9. In regulation 24 of the said regulations,—

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) On and from the 1st day of November, 2012, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer’s own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:—

TABLE

Grade	Maximum limit of reimbursement
(1)	(2)
Junior Management and Middle Management Grade	Rs. 8000 per annum or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs. 9050 per annum or the amount incurred whichever is less

Note: (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above; or

(ii) for the year 2012, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November, 2012 and December, 2012.

(1A) An Officer is eligible for Medical Insurance facility for self and his family, as per the terms and conditions specified by the Board.”

10. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2012, a sum equal to 0.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.15 per cent of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”.

11. In regulation 33 of the said regulations, for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(4) On and from 1st June, 2015, Privilege Leave may be accumulated up to not more than 270 days except where leave has been applied and it has been refused:

Provided that encashment of Privilege Leave shall be restricted up to a maximum of 240 days:

Provided further that an officer desiring to avail Privilege Leave shall ordinarily give not less than 15 days notice of his intention to avail such leave.”.

12. In regulation 34 of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(4) On and from 1st June, 2015, Special Sick Leave up to 30 days may be granted to an officer once during his entire period of service for donation of kidney or organ.”.

13. In regulation 36 of the said regulations, for sub-regulations (2) and (3), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

“(2) With effect from the 25th May 2015, leave may also be granted once during service to a childless female officer for legally adopting a child who is below one year of age for a maximum period of six months subject to the following terms and conditions:—

- (i) leave will be granted for adoption of only one child;
- (ii) the adoption of a child should be through a proper legal process and the employee should produce the adoption deed to the Bank for sanctioning such leave;
- (iii) the leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy; and
- (iv) the leave shall be availed within overall entitlement of twelve months during the entire period of service.

(3) With effect from the 25th May 2015, within the overall period of twelve months, leave may also be granted in case of hysterectomy up to a maximum of sixty days.

(4) Maternity leave, which shall be on substantive pay, shall be granted to a female officer for a period not exceeding six months on any one occasion and twelve months during the entire period of her service:

Provided that within the overall period of twelve months, leave may also be granted in case of miscarriage or abortion or Medical Termination of Pregnancy.

(5) With effect from 1st June 2015, male officers having up to two surviving children shall be eligible for fifteen days paternity leave during his wife's confinement which may be combined with any other kind of leave except casual leave:

Provided that the leave shall be applied up to fifteen days before or up to six months from the date of delivery of the child.”.

14. For regulation 38 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

“(38) Lapse of Leave.— Save as provided below, all leave to the credit of an officer shall lapse on resignation, retirement, death, discharge, dismissal or termination:

Provided that where an officer retires from the Bank’s service, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments of any period, not exceeding 240 days of privilege leave that he had accumulated:

Provided further that where an officer has been compulsorily retired including as a measure of punishment, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to emoluments of any period, not exceeding 240 days of privilege leave that he has accumulated:

Provided also that where an officer dies while in service, there shall be payable to his legal representatives, a sum equivalent to the emoluments for the period not exceeding 240 days of privilege leave to his credit as on the date of his death:

Provided also that where an officer resigns from service on or after 1st April, 2001 after giving due notice as in sub-regulation (2) of regulation 20, he may be paid a sum equivalent to the emoluments in respect of privilege leave to the extent of half of such leave to his credit on the date of cessation of service, subject to a maximum of 120 days.”.

15. In regulation 41 of the said regulations,—

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) On and from 1st day of November 2012, wherever an officer is required to travel on duty, the following provisions shall apply, namely:—

- (a) an Officer in Junior Management Grade is entitled to travel by 1st class or AC 2-tier Sleeper by train:

Provided that he may travel by air (economy class) if so permitted by Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

- (b) an officer in Middle Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC2-tier Sleeper by train:

Provided that he may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 1000 kilometers:

Provided further that he may travel by air (economy class) even for shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

- (c) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st Class by train or by air (economy class);

- (d) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 kilometers:

Provided that when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car;

- (e) any other officer may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank’s vehicle;

- (f) an officer of any grade or scale shall be eligible to travel by water transport in deluxe cabin category between places not connected by road or air or rail.”;

(ii) insub-regulation (4), for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:

“(a) On and from the 1st June, 2015, an officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the table below shall be entitled to per diem Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:—

TABLE

Grade/Scales of Officers	Metro (Rs.)	Major 'A' Class Cities (Rs.)	Area -I (Rs.)	Other Places (Rs.)
(1)	(2)			
Officers in Scale VI and above	1800	1300	1100	950
Officers in Scale IV and V	1500	1300	1100	950
Officers in Scale I, II and III	1300	1100	950	800

Provided that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation: – For the purposes of computing Halting Allowance “per diem” shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, “per diem” shall mean a period of not less than eight hours.

(b) On and from the 31st day of March, 2020, an Officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the table below may be reimbursed the actual hotel expenses restricting to single room accommodation charges in India Tourism Development Corporation hotels of the corresponding star category set out in column (2) thereof, as under:

TABLE

GRADES / SCALES OF OFFICERS	ELIGIBILITY TO STAY
(1)	(2)
Scale-VI, VII and VIII	4 Star Hotel
Scale-IV and V	3 Star Hotel
Scale-II and III	2 Star Hotel (Non AC)
Scale-I	1 Star Hotel (Non AC)

Provided that the Board may specify the additional limit to be reimbursed in excess of the limits specified above, in accordance with the guidelines of the Central Government.”.

16. In regulation 42 of the said regulations, for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:–

“(3) On and from the 1st day of June, 2015, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the table below, namely:–

TABLE

Grade/Scale	Amount
(1)	(2)
Top Executive and Senior Management Grade (Officers in Scale IV and above)	Rs.20,000
Middle Management and Junior Management Grade (Officers upto Scale III)	Rs.15,000”

17. In regulation 44 of the said regulations, for sub-regulation (3), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

“(3) During each block of four years, an officer shall be eligible for leave travel concession for travel to his place of domicile once in each block of two years:

Provided that, he may travel in one block of two years to his place of domicile and in another block of two years to any place in India by the shortest route:

Provided further that with effect from 1st June, 2015, alternatively, an officer by exercising an option anytime during a four year block or two year block, as the case maybe, surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to place of domicile) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled up to a distance of 4,500 kilometers (one-way) for officers in JMG-Scale I and MMG-Scale II and III and 5,500 kilometers (one-way) for officers in SMG-Scale IV and above:

Provided also that with effect from 1st June, 2015, an officer opting to encash his Leave Travel Concession, shall prefer the claim for himself and his family members only once during the block in which such encashment is availed of and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Travel Concession is also available while encashing the facility of Leave Travel Concession.

(3A) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer, shall be as decided by the Board from time-to-time:

Provided that with effect from 1st May, 2010, an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement will be the actual fare or the fare applicable to AC 1st Class fare by train for the distance travelled whichever is less and the same rules shall apply when an Officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III while availing Leave Travel Concession where the distance is less than 1000 kilometers.”.

18. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE

[See regulation 23(2)]

With effect from the 1st day of November, 2012, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:—

TABLE

Sl.No.	Area	Allowances(in rupees)	
		Pay below Rs. 24,000	Pay above Rs. 24,000
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mizoram		
	(a) Chimpui District and areas beyond 25 kilometers from Lunglei Town in Lunglei District.	2000	2600
	(b) Entire Lunglei District excluding areas beyond 25 kilometers from Lunglei town.	1600	2100
	(c) Entire Aizawl District	1200	1500

2.	Nagaland	1600	2100
3.	Andaman and Nicobar Islands (a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands (b) South Andaman(including Port Blair)	2000 1600	2600 2100
4.	Sikkim	2000	2600
5.	Lakshadweep Islands	2000	2600
6.	Assam	320	400
7.	Meghalaya	320	400
8.	Tripura (a) Difficult areas of Tripura (b) Throughout Tripura except difficult areas.	1600 1200	2100 1500
9.	Manipur	1200	1500
10.	Arunachal Pradesh (a) Difficult areas of Arunachal Pradesh (b) Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas.	2000 1600	2600 2100
11.	Jammu and Kashmir (a) Kathua District: NiabatBani, Lohi, Malhar and Machhodi (b) Udhampur District: (i) DuduBasantgarh, Lander BhamagIllaqa, other than those included in Part 2(b). (ii) Areas up toGoel from Kamban Side and areas up to Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre. (c) Doda District: Illaquas of Padder and NiabatNowgam in Kishtwar Tehsil (d) Leh District: All places in the District (e) Barmulla District (i) Entire Gurez– Nirabat , Tangdar Sub–Division and KeranIllaqua (ii) Matchill (f) Poonch and Rajouri District: Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.	2000 2000 1600 2000 2000 1600 1200	2600 2600 2100 2600 2600 2100 1500

	(g) Areas not included in items (a) to (f) above, but which are within the distance of 8 kilometers from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.	1200	1500
12.	Himachal Pradesh 1. Chamba District (a) Pangi Tehsil, Bharmour Tehsil, Panchayats: Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata (b) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in (a) above. (c) Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).	2000 1600 1200	2600 2100 1500
	2. Kinnaur District: (i) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/Charang Panchayats, 15/20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above. (ii) Entire District other than Areas included in (i) above.	2000 1600	2600 2100
	3. Kullu District: (i) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga (ii) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Saraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	2000 1200	2600 1500
	4. Lahaul and Spiti District: Entire area of Lahaul and Spiti	2000	2600
	5. Shimla District: (i) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda. (ii) Dora-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana Sarahan. (iii) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	2000 1600 1200	2600 2100 1500

	<p>6. Kangra District:</p> <p>(i) Areas of Bara Bhangal and ChhotaBhangal</p> <p>(ii) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town—Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari,I.P.H— Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar.</p> <p>Palampur Town of Kangra District including HPKVV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town –H.P.</p> <p>KrishiVishwavidhalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar.</p>	<p>1600</p> <p>1200</p>	<p>2100</p> <p>1500</p>
	<p>7. Mandi District:</p> <p>Chhuvar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in Thunag Tehsil— of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth,Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block—Binga, Kamlah,Saklana,Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil— Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi,Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil— Bohi, Batwara, Dhanyara, PauraKothi,Seri and Shoja.</p>	<p>1200</p>	<p>1500</p>
	<p>8. Sirmaur District:</p> <p>Panchayats of Bani, Bakhali,(Pachhad Tehsil), BharogBheneri(Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber(Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil) and Thansgiri Tract</p>	<p>1200</p>	<p>1500</p>
	<p>9. Solan District</p> <p>MangalPanchayat</p>	<p>1200</p>	<p>1500</p>
	<p>10. Remaining areas of Himachal Pradesh not included in items (1) to (9) above.</p>	<p>320</p>	<p>400</p>
13.	<p>Uttar Pradesh</p> <p>Areas under Chamoli, Pithoragarh and Uttar Kashi Districts</p>	<p>2000</p>	<p>2600</p>
14.	<p>Uttarakhand</p> <p>Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts.</p>	<p>2000</p>	<p>2600”</p>

EXPLANATORY MEMORANDUM

The retrospective effect given in these regulations relate to the pay and other allowances and benefits to the officers of the Union Bank of India and are essentially beneficial legislation. Hence, giving retrospective effect to the said provisions of these regulations will not adversely affect the interest of any person as a result of such retrospective application.

S. K. MOHAPATRA, Field General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./526/19]

Note: The amendment regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 *vide* following notifications, namely:—

Sr. No.	Notification No.	Date
1.	OSR/1	14.11.1987
2.	OSR/2	04.06.1988
3.	OSR/3	04.06.1988
4.	OSR/4	30.12.1989
5.	OSR/5	27.10.1990
6.	OSR/6	11.01.1992
7.	OSR/7	12.12.1992
8.	OSR/8	27.02.1993
9.	OSR/9	25.09.1993
10.	OSR/10	10.09.1994
11.	OSR/11	07.01.1995
12.	OSR/12	07.09.1996
13.	OSR/13	21.12.1996
14.	OSR/14	21.12.1996
15.	OSR/15	21.12.1996
16.	OSR/15	06.02.1996
17.	OSR/16	03.06.2000
18.	OSR/16	30.12.2000
19.	OSR/17	09.12.2000
20.	OSR/18	29.10.2002
21.	OSR/19	18.06.2003
22.	OSR/20	27.01.2006
23.	OSR/21	10.03.2007
24.	OSR/22	25.09.2017